Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language,
Online ISSN 2348-3083, SJ IMPACT FACTOR 2021: 7.278, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL, FEB-MAR, 2022, VOL-10/50

उच्च शिक्षा पर नई शिक्षा नीति (2020) का प्रभाव

मनोज कुमार सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर(बी.एड.), राठ महाविद्यालय, पैठाणी, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड

Paper Received On: 25 MAR 2022

Peer Reviewed On: 31 MAR 2022

Published On: 1 APR 2022

Abstract

भारत सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति (एनईपी 2020) कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के कारण दुनिया भर में सभी नकारात्मकताओं के बीच एक स्वागत योग्य बदलाव और ताजा खबर थी। एनईपी 2020 की घोषणा पूरी तरह से कई लोगों द्वारा अप्रत्याशित थी। एनईपी 2020 ने जिन बदलावों की सिफारिश की है, वे कुछ ऐसे थे जिन्हें कई शिक्षाविदों ने कभी आते नहीं देखा। हालाँकि शिक्षा नीति ने स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को समान रूप से प्रभावित किया है, यह लेख मुख्य रूप से (एनईपी 2020) और उच्च शिक्षा पर इसके प्रभाव पर केंद्रित है। यह पेपर एनईपी की मुख्य विशेषताओं को भी रेखांकित करता है और विश्लेषण करता है कि वे मौजूदा शिक्षा प्रणाली को कैसे प्रभावित करते हैं।

मुख्य शब्द- *नई शिक्षा नीति, उच्च शिक्षा, कोविड-19*

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

प्रस्तावना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) भारत के लोगों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा तैयार की गई एक नीति है। नीति में ग्रामीण और शहरी भारत दोनों के कॉलेजों में प्रारंभिक शिक्षा शामिल है। पहला एनपीई भारत सरकार द्वारा 1968 में प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी द्वारा, दूसरा प्रधान मंत्री राजीव गांधी द्वारा 1986 में और तीसरा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2020 में प्रख्यापित किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020), जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, भारत की नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। नई नीति शिक्षा पर पिछली राष्ट्रीय नीति 1986 की जगह लेती है। नीति ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में प्रारंभिक शिक्षा से उच्च शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक ढांचा है। नीति का उद्देश्य 2021 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना है। एनईपी में भाषा नीति प्रकृति में एक व्यापक दिशानिर्देश और सलाहकार है और यह राज्यों, संस्थानों और स्कूलों के कार्यान्वयन पर निर्णय लेने के लिए है। एनईपी 2020 कई अधिनियमों को लागू करता है। भारत की शिक्षा नीति में बदलाव में इसका उद्देश्य शिक्षा पर राज्य के खर्च को जल्द से जल्द सकल घरेलू उत्पाद के 4% से 6% तक बढ़ाना है। जनवरी 2015 में, पूर्व कैबिनेट सचिव टी.एस.आर. सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक समिति ने नई शिक्षा नीति के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू की। जून 2017 में समिति की रिपोर्ट के आधार पर एनईपी का मसौदा 2019 में पूर्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

(इसरो) के प्रमुख कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में एक पैनल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मसौदा नई शिक्षा नीति (डीएनईपी) 2019 को बाद में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। मंत्रालय ने मसौदा नीति तैयार करने में एक कठोर परामर्श प्रक्रिया शुरू की जिसमें 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6,600 ब्लॉक, 6,000 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) 676 जिलों से दो लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए । राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दृष्टिकोण है:- "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके हमारे देश को एक समान और जीवंत ज्ञान समाज में बदलने में सीधे योगदान देती है।"

गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को विकसित करना होना चाहिए जो उत्कृष्ट विचारशील, अच्छी तरह से गोल और रचनात्मक हों। यह एक व्यक्ति को एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों का गहराई से अध्ययन करने और चरित्र नैतिक और संवैधानिक मूल्यों को विकसित करने में सक्षम होना चाहिए जिसमें बौद्धिक जिज्ञासा वैज्ञानिक स्वभाव, रचनात्मकता सेवा भावना और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, भाषा, व्यक्तिगत तकनीकी, व्यावसायिक विषयों सहित कई क्षेत्रों में 21वीं सदी का कौशल आदि मूल्यों को शामिल किया जाना चाहिए। प्रत्येक जिले में या उसके आस-पास छात्र पाठ्यचर्या के मूल्यांकन में सुधार करना और छात्रों के अनुभव को बढ़ाने के लिए समर्थन करना, उत्कृष्ट सहकर्मी समीक्षा कार्य और विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रभावी ढंग से गहन अध्ययन का समर्थन करने के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना करना। भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली द्वारा सामना की जाने वाली मुख्य समस्याओं में योग्यताओं को प्रारंभिक विशेषज्ञता और प्रतिबंधित अनुसंधान क्षेत्रों में छात्रों की स्ट्रीमिंग को लागू करना शामिल है। अधिकांश विश्वविद्यालयों और स्कूलों में अनुसंधान पर कम ध्यान देना और प्रतिस्पर्धी समकक्षों की समीक्षा शैक्षणिक अनुसंधान निधि और बड़े संबद्ध विश्वविद्यालयों की कमी जो निम्न स्तर की ओर ले जाती है। संस्थागत पुनर्गठन और समेकन का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों को बड़े बहु-विषयक में बदलकर अच्छी तरह से गोल और नवीन व्यक्तियों का निर्माण करना और अन्य देशों को शैक्षिक और आर्थिक रूप से उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% (2018) से 2035 तक 50% तक व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित बढ़ाना है। समग्र और बहु-विषयक शिक्षा को सभी मानवीय क्षमताओं, मानसिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और नैतिक सुधार के लिए एकीकृत तरीके से प्रयास करना चाहिए। लंबी अवधि में ऐसी व्यापक शिक्षा चिकित्सा तकनीकी और व्यावसायिक विषयों सहित सभी स्नातक कार्यक्रमों के लिए पद्धति होगी। छात्रों के लिए इष्टतम सीखने का वातावरण और समर्थन एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है जिसमें पर्याप्त पाठ्यक्रम इंटरैक्टिव शिक्षाशास्त्र, सुसंगत रचनात्मक मूल्यांकन और छात्रों के लिए पर्याप्त समर्थन शामिल है।

अध्ययन का उद्देश्य- इस शोध का प्राथमिक उद्देश्य उच्च शिक्षा पर नई शिक्षा नीति 2020 के प्रभाव का अध्ययन करना है। अध्ययन एनईपी की मुख्य विशेषताओं को भी रेखांकित करता है और विश्लेषण करता है कि वे मौजूदा शिक्षा प्रणाली को कैसे प्रभावित करते हैं।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

शोध प्राविधि-

यह शोध एक वर्णनात्मक अध्ययन है। भारत सरकार की पत्रिकाओं, अन्य प्रकाशनों आदि सहित विभिन्न वेबसाइटों से आवश्यक माध्यमिक आंकड़ा एकत्र किया गया है। इसके बाद निष्कर्षों और निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए इस आंकड़े का विश्लेषण और समीक्षा की गई है।

उच्च शिक्षा से संबंधित एनईपी की मुख्य विशेषताएं

नई एनईपी को स्कूल स्तर से कॉलेज/विश्वविद्यालय स्तर तक की प्रणाली में परिवर्तनों को औपचारिक रूप देने के उद्देश्य से पेश किया गया है। विकासशील परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, अब से शिक्षा सामग्री मुख्य-अवधारणाओं, विचारों, अनुप्रयोगों और समस्या-समाधान के कोणों पर ध्यान केंद्रित करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से देश की उच्च शिक्षा प्रणाली पर सकारात्मक और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। यह तथ्य कि विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर खोलने की अनुमति दी जाएगी, सरकार द्वारा एक सराहनीय पहल है। इससे छात्रों को अपने ही देश में शिक्षा की वैश्विक गुणवत्ता का अनुभव करने में मदद मिलेगी। बहु-विषयक संस्थानों को शुरू करने की नीति से कला, मानविकी जैसे हर क्षेत्र पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित होगा और शिक्षा के इस रूप से छात्रों को सीखने और समग्र रूप से विकसित होने में मदद मिलेगी। इस प्रकार, छात्रों को मजबूत ज्ञान आधार से सुसज्जित किया जाएगा। सिंगल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की शुरुआत एक और सकारात्मक कदम है जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं के तनाव को कम करेगा और उनमें से कई की तैयारी के दबाव को कम करेगा। यह आगे जाने वाले सभी छात्र आवेदकों के लिए एक समान खेल मैदान भी सुनिश्चित करेगा। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) की स्थापना निश्चित रूप से अकादमिक क्रेडिट को स्टोर करने के लिए एक मजबूत विचार है जो छात्र विभिन्न मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों से पाठ्यक्रम लेकर कमाते हैं। एक छात्र पाठ्यक्रम पूरा करके अंक अर्जित कर सकता है और इन्हें एबीसी खाते में जमा किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति कॉलेज स्विच करने का निर्णय लेता है तो वह इन क्रेडिट को स्थानांतरित कर सकता है। यदि कोई छात्र कभी किसी कारण से स्कूल छोड़ देता है, तो ये क्रेडिट बरकरार रहेंगे, जिसका अर्थ है कि वह वर्षों बाद वापस आ सकता है और जहां से छात्र छोड़ा था, वहां से उठा सकता है। नई उच्च शिक्षा नियामक संरचना यह सुनिश्चित करेगी कि अलग-अलग, स्वायत्त और अधिकार प्राप्त निकायों द्वारा अलग-अलग प्रशासनिक, मान्यता, वित्तपोषण और शैक्षणिक मानक-सेटिंग भूमिकाएं निभाई जाती हैं। इन चार संरचनाओं को एक एकल संस्थान, भारत के उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) के भीतर चार स्वतंत्र वर्टिकल के रूप में स्थापित किया जाएगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एनईपी द्वारा कई सुधार और नए विकास किए गए हैं। कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

• उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक निकाय:

एनईपी का उद्देश्य भारत के उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना करना है जो कानूनी और चिकित्सा शिक्षा को छोड़कर एकल नियामक निकाय होगा ।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

• एकाधिक प्रविष्टि और निकास कार्यक्रम

उन लोगों के लिए कई प्रविष्टि और निकास विकल्प होंगे जो मध्य में पाठ्यक्रम छोड़ना चाहते हैं। उनके क्रेडिट अकादमिक बैंक क्रेडिट के माध्यम से स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

• ऐप्स, टीवी चैनलों के माध्यम से वयस्क सीखने के लिए टेक- आधारित विकल्प

ऐप्स, ऑनलाइन पाठ्यक्रम / मॉड्यूल, उपग्रह आधारित टीवी चैनल, ऑनलाइन किताबें, और आईसीटी-सुसज्जित पुस्तकालयों और वयस्क शिक्षा केंद्र आदि जैसे वयस्क सीखने के लिए गुणवत्ता प्रौद्योगिकी-आधारित विकल्प विकसित किए जाएंगे।

• ई-पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होने के लिए

प्रौद्योगिकी शिक्षा योजना, शिक्षण, सीखने, मूल्यांकन, शिक्षक, स्कूल और छात्र प्रशिक्षण का हिस्सा होगा। ई-सामग्री क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होने के लिए, 8 प्रमुख भाषाओं से शुरू होती है - कन्नड़, ओडिया, बंगाली हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध ई-पाठ्यक्रमों में शामिल होने के लिए।

• भारत में परिसरों को स्थापित करने के लिए विदेशी विश्वविद्यालय

दुनिया के शीर्ष 100 विदेशी विश्वविद्यालयों को एक नए कानून के माध्यम से भारत में काम करने के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी। एचआरडी मंत्रालय के दस्तावेज के अनुसार, "इस तरह के (विदेशी) विश्वविद्यालयों को भारत के अन्य स्वायत्त संस्थानों के बराबर नियामक, शासन और सामग्री मानदंडों के संबंध में विशेष विवाद दिया जाएगा।"

• सभी कॉलेजों के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए आम प्रवेश परीक्षा । परीक्षा वैकल्पिक होगी ।

• उच्च शिक्षा परिषद (एचईसीआई) उच्च शिक्षा को विनियमित करने के लिए स्थापित किया जाएगा। परिषद का लक्ष्य सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि होगी। एचईसीआई में 4 वर्टिकल होंगे:

ए- चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर, शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद (एनएचईआरसी)।

बी- राष्ट्रीय मान्यता परिषद (एनएसी), एक "मेटा-मान्यता प्राप्त शरीर"।

सी- विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के वित्त पोषण और वित्त पोषण के लिए उच्च शिक्षा अनुदान परिषद (एचईजीसी)। यह मौजूदा राष्ट्रीय परिषद के शिक्षक शिक्षा, अखिल भारतीय परिषद तकनीकी शिक्षा और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जगह लेगा।

डी- सामान्य शिक्षा परिषद (जीईसी), "स्नातक विशेषताओं" को फ्रेम करने के लिए, अर्थात् सीखने के परिणामों की उम्मीद है। यह एक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता ढांचे (एनएचईक्यूएफ) को तैयार करने में भी जिम्मेदार होगा। शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद एक पेशेवर मानक सेटिंग बॉडी (पीएसएसबी) के रूप में जीईसी के तहत आएगी।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

उच्च शिक्षा पर एनईपी के प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण-

उच्च शिक्षा की नियामक प्रणाली

एनईपी 2020 में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए एक छतरी निकाय के रूप में, भारत (एचईसीआई) की उच्च शिक्षा आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह आमतौर पर एक प्रश्न लाता है कि वर्तमान यूजीसी और एआईसीटीई के साथ क्या होगा? एचईसीआई उच्च शिक्षा क्षेत्र में सुधार करने का लक्ष्य रख रहा है; बिल इस क्षेत्र के अकादमिक और वित्त पोषण पहलुओं को अलग करेगा। नए बिल के अनुसार, एचईसीआई की कोई वित्तीय शक्तियां नहीं होंगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा संभाले गए वित्त पोषण प्रक्रियाओं को शिक्षा मंत्रालय द्वारा सावधानी बरत दी जाएगी, जिसे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के रूप में जाना जाता था। हालांकि यह परिवर्तन भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में नियामक गड़बड़ी को दूर करने की उम्मीद है। एचईसीआई में चार स्वतंत्र वर्टिकल होने की उम्मीद है - राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद (एनएचईआरसी) मानक सेटिंग के लिए सामान्य शिक्षा परिषद (जीईसी), वित्त पोषण के लिए उच्च शिक्षा अनुदान परिषद (एचईजीसी), और प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रीय मान्यता परिषद (एनएसी) । शिक्षा मानकों में एकरूपता रखने के लिए, एक छतरी शरीर हमेशा एक आवश्यकता थी और यह कई शिक्षाविदों की दृष्टि रही है। इसे शिक्षा नीति को सुव्यवस्थित करने में सही कदम माना जाता है। हालांकि, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, संस्थानों को अनुसंधान, उद्योग संबंधों, प्लेसमेंट और अकादमिक उत्कृष्टता आदि जैसे प्रासंगिक मानकों के आधार पर मापा जाना चाहिए। यदि एचईसीआई इसका प्रबंधन कर सकता है तो इसके सबसे बड़े हितधारक भारत के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

वर्गीकृत मान्यता और वर्गीकृत स्वायत्तता

"सशक्तिकरण और स्वायत्तता के लिए स्वायत्तता" की अवधारणा एनईपी 2020 में प्रमुख विशेषताओं में से एक है जो संबद्ध कॉलेजों से स्वायत्त संस्थानों में "चरणबद्ध आउट" रणनीति का समर्थन करती है। स्वायत्त संस्थानों को दी गई लचीलापन भी पाठ्यचर्या संवर्द्धन में आशा देता है। यह भी कहता है कि उचित मान्यताओं के साथ, स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले कॉलेज अनुसंधान-केंद्रित या शिक्षण-केंद्रित विश्वविद्यालयों में विकसित हो सकते हैं, अगर वे इतनी आकांक्षा रखते हैं। देश में बहुआयामी शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों (मेरस) की स्थापना की घोषणा अधिक आशा देती है। ये संस्थान मौजूदा आईआईटी और आईआईएमएस के बराबर होंगे और भारतीय छात्रों के लिए बहुआयामी शिक्षा का प्रदर्शन करने का लक्ष्य रखेंगे।

एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन एनईपी 2020 से पता चलता है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी उच्च शिक्षा संस्थानों में स्नातक और स्नातक प्रवेश और फैलोशिप के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए एक प्रमुख, विशेषज्ञ, स्वायत्त परीक्षण संगठन के रूप में कार्य करेगी। एनटीए परीक्षण सेवाओं की उच्च गुणवत्ता, सीमा और लचीलापन अधिकतर विश्वविद्यालयों को इन आम प्रवेश परीक्षाओं का उपयोग करने में सक्षम करेगा - प्रत्येक विश्वविद्यालय के अपने प्रवेश परीक्षाओं को तैयार करने के बजाय - इस प्रकार छात्रों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों पर बोझ को काफी हद तक कम कर देगा, और पूरी शिक्षा प्रणाली। यह उनके प्रवेश के लिए एनटीए आकलन का उपयोग करने के

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

लिए व्यक्तिगत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों तक छोड़ दिया जाएगा। यह निश्चित रूप से छात्रों को विदेशों में विश्वविद्यालयों में आसानी से अपनी डिग्री और क्रेडिट स्थानांतरित करने में मदद करता है।

घर पर अंतर्राष्ट्रीयकरण

एनईपी 2020 विदेशी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को भारत आने की इजाजत देता है और यह मूल संस्थानों के लिए प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक चुनौती लाता है। भारतीय उच्च शिक्षा क्षेत्र देश में परिसरों को स्थापित करने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए मार्ग प्रशस्त करने का अवसर के रूप में चारों ओर घूम रहा है। भारत में 900 से अधिक विश्वविद्यालयों और 40,000 कॉलेजों के साथ भारत में उच्च शिक्षा प्रणालियों में से एक है। लेकिन उच्च शिक्षा में भारत की Ger (सकल नामांकन अनुपात) 26.3% है, जो ब्राजील (50%) या चीन (51%) जैसे अन्य ब्रिक्स देशों की तुलना में काफी कम है, और यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी की तुलना में बहुत कम है राष्ट्र जो 80% से अधिक होंगे। भारत को एक सतत आर्थिक विकास के लिए वैश्विक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल करनी चाहिए, जिसे प्राकृतिक संसाधनों द्वारा संचालित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ज्ञान संसाधनों द्वारा। रिपोर्टों के अनुसार, भारत को छात्रों के एक विशाल प्रवाह को समायोजित करने के लिए 2030 तक 1,500 से अधिक नए शिक्षा संस्थानों की आवश्यकता होगी, यही कारण है कि भारत सरकार एफडीआई (विदेशी प्रत्यक्ष निवेश) को बढ़ावा देना चाहती है और ईसीबी (बाहरी वाणिज्यिक उधार) खोलना चाहती है जो शिक्षा क्षेत्र के लिए पूंजीगत निवेश को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करे।

मंत्रालय भी भारत की छवि को एक शिक्षा केंद्र के रूप में बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है क्योंकि पहले से ही 7 लाख से अधिक भारतीय छात्र विदेशों में पढ़ रहे हैं। इसलिए, इस नीति का इरादा यह है कि विदेशी विश्वविद्यालयों की अनुमति देने से विश्व स्तरीय शिक्षा स्थानीय रूप से यात्रा के बिना काफी कम लागत पर उपलब्ध कराएगी और अध्ययन और नौकरी की संभावनाओं के लिए अन्य देशों में माइग्रेट करने वाली मानव पूंजी को काफी कम कर देगी। विभिन्न वैश्विक सर्वेक्षणों के मुताबिक, सीमा पार शिक्षा अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है और वैश्विक जागरूकता, सांस्कृतिक रूप से अवधारणात्मक, और प्रतिस्पर्धात्मकता का व्यापक स्तर लाती है। विदेशी सहयोग स्थानीय संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय अध्यापन के साथ संरेखण में अपने पाठ्यक्रम को डिजाइन करने और छात्रों के लिए विषयों और विशेषज्ञता के एक विविध पोर्टफोलियो की पेशकश करने में सक्षम बनाता है।

अधिक समग्र और बहुआयामी शिक्षा

एनईपी 2020 का दावा है कि एक समग्र और बहुआयामी शिक्षा एक एकीकृत तरीके से बौद्धिक, सौंदर्य सामाजिक शारीरिक भावनात्मक और नैतिक मानव प्राणियों की सभी क्षमताओं को विकसित करना है। ऐसी शिक्षा अच्छी तरह से गोल किए गए व्यक्तियों को विकसित करने में मदद करेगी जिनके पास कला मानविकी भाषाओं में खेतों में 21 वीं शताब्दी की क्षमताएं हैं मानविकी विज्ञान विज्ञान सामाजिक विज्ञान और व्यावसायिक तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्र सामाजिक सगाई नरम कौशल का नैतिकता जैसे संचार चर्चा और बहस और कठोर विशेषज्ञता चुना गया क्षेत्र या खेत। एनईपी 2020-2030 तक हर जिले में या उसके आस-पास एक बड़ी बहुआयामी उच्च शिक्षा संस्थान (एचईआई) की कल्पना करता है। इस तरह की एक समग्र और बहुसंख्यक शिक्षा की प्राप्ति में सभी हेरियों

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

के लचीले और अभिनव पाठ्यक्रम में क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम और परियोजनाओं के क्षेत्रों में शामिल होंगे सामुदायिक सगाई और सेवा, पर्यावरण शिक्षा और मूल्य-आधारित शिक्षा। पर्यावरण शिक्षा में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण अपशिष्ट प्रबंधन स्वच्छता जैव विविधता प्रबंधन के जैविक विविधता प्रबंधन के जैव विविधता जंगल और वन्यजीव संरक्षण और सतत विकास और जीवन के क्षेत्रों में शामिल होंगे। मूल्य आधारित शिक्षा में मानववादी नैतिक, संवैधानिक और सार्वभौमिक मानव मूल्यों के विकास (सत्य) धर्मी आचरण (शांति) शांति (शांति) प्रेम (प्रेम) वैज्ञानिक स्वभाव नागरिकता मूल्यों और जीवन-कौशल के सबक और जीवन-कौशल के सबक भी शामिल होंगे सामुदायिक सेवा कार्यक्रमों में सेवा / सेवा और भागीदारी को समग्र शिक्षा का एक अभिन्न हिस्सा माना जाएगा।

चूंकि दुनिया तेजी से जुड़े हुए हो रही है, वैश्विक नागरिकता शिक्षा (जीईसी) शिक्षकों को वैश्विक मुद्दों के बारे में जागरूक और समझने और अधिक शांतिपूर्ण सहिष्णु समावेशी सुरक्षित और टिकाऊ समाजों के सक्रिय प्रमोटर बनने के लिए शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए समकालीन वैश्विक चुनौतियों का जवाब प्रदान किया जाएगा। अंत में एक समग्र शिक्षा के हिस्से के रूप में सभी हेर्स में छात्रों को स्थानीय उद्योग, व्यवसाय कलाकार शिल्प व्यक्तियों के साथ इंटर्नशिप के अवसरों के साथ-साथ संकाय और शोधकर्ताओं के साथ अनुसंधान इंटर्नशिप के साथ-साथ अपने या अन्य हेर्स / शोध संस्थानों के साथ अनुसंधान इंटर्नशिप भी प्रदान किए जाएंगे ताकि छात्र हो सकें सक्रिय रूप से अपने सीखने के व्यावहारिक पक्ष के साथ संलग्न हैं और उप-उत्पाद के रूप में अपनी नियोक्तायता में सुधार करते हैं।

डिग्री प्रोग्राम की संरचना और लंबाई

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 योजना के संदर्भ में किसी भी संस्थान में किसी भी स्नातक की डिग्री तीन या चार वर्षों की अवधि होगी। कोई इस अवधि के भीतर की डिग्री छोड़ सकता है। किसी भी शैक्षिक संस्थान को छात्र को दो साल का अध्ययन पूरा करने के बाद छात्र को डिप्लोमा डिग्री देना होगा, छात्र को तीन साल का अध्ययन पूरा करने के बाद डिग्री और उन छात्रों को प्रमाण पत्र जो किसी भी पेशेवर या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में एक वर्ष का अध्ययन पूरा करता है उनकी पसंद। भारत सरकार अकादमिक स्कोर डिजिटल रूप से संग्रहीत करने के लिए अकादमिक बैंक क्रेडिट की स्थापना में भी मदद करेगी। यह संस्थानों को अंत में क्रेडिट गिनने में सक्षम करेगा और इसे छात्र की डिग्री में डाल देगा। यह उन व्यक्तियों के लिए सहायक होगा जिन्हें पाठ्यक्रम मध्य मार्ग छोड़ना पड़ सकता है। वे बाद में पाठ्यक्रम शुरू कर सकते हैं जहां से वे छोड़े गए थे और एक बार फिर से शुरुआत से शुरू नहीं होते हैं। हालांकि एनईपी 2020 का कहना है कि उच्च शिक्षा संस्थानों को पीजी पाठ्यक्रम शुरू करने की स्वतंत्रता दी जाएगी, वहां उन छात्रों के लिए एक वर्ष पीजी डिग्री डिजाइन करने में कुछ कठिनाई हो सकती है जिन्होंने 4 साल की यूजी डिग्री पूरी की है और 3 साल के छात्रों के लिए दो साल की पीजी डिग्री पूरी की है।

निष्कर्ष

नीति परिवर्तनों की एक पूरी श्रृंखला पेश करती है और वर्तमान सामाजिक आर्थिक परिदृश्य और भविष्य की अनिश्चितता की संभावना पर एक मजबूत पकड़ के साथ एक बहुत ही प्रगतिशील दस्तावेज के रूप में पढ़ती है। शिक्षार्थियों की एक नई पीढ़ी के लिए शिक्षा को अनिवार्य रूप से अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते अभौतिकीकरण और

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

डिजिटलीकरण के साथ जुड़ना होगा, जिसे बनाए रखने में सक्षम होने के लिए क्षमताओं के एक पूरी तरह से नए सेट की आवश्यकता होती है। यह अब और भी अधिक महत्वपूर्ण अनुलाभ प्रतीत होता है क्योंकि डिजिटलीकरण और विघटनकारी स्वचालन की ओर रुझान महामारी द्वारा तेज किया जा रहा है। कुल मिलाकर एनईपी 2020 कृषि से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक विभिन्न क्षेत्रों में पेशेवरों को विकसित करने की आवश्यकता को संबोधित करता है। भारत को भविष्य के लिए तैयार रहने की जरूरत है और एनईपी 2020 कई युवा इच्छुक छात्रों के लिए सही कौशल से तैयार होने का मार्ग प्रशस्त करता है।

नई शिक्षा नीति में एक प्रशंसनीय दृष्टि है, लेकिन इसकी ताकत इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या यह सरकार की अन्य नीतिगत पहलों जैसे डिजिटल इंडिया स्किल इंडिया और नई औद्योगिक नीति के साथ प्रभावी ढंग से एकीकृत करने में सक्षम है, ताकि एक सुसंगत संरचनात्मक परिवर्तन को प्रभावित किया जा सके। इसलिए नीतिगत संबंध यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि शिक्षा नीति इसे सफल बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम को आकार देने के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र के साथ अधिक गतिशील रूप से जुड़ने में स्किल इंडिया के अनुभव को संबोधित करती है और उससे सीखती है। तेजी से विकसित हो रहे रूपांतरणों और व्यवधानों के अनुकूल होने के लिए अधिक साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने की भी आवश्यकता है। एनईपी ने वास्तविक समय मूल्यांकन प्रणाली और एक परामर्शी निगरानी और समीक्षा ढांचे के लिए आश्वस्त रूप से प्रावधान किया है। यह शिक्षा प्रणाली को पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए हर दशक में एक नई शिक्षा नीति की अपेक्षा करने के बजाय, अपने आप में लगातार सुधार करने के लिए सशक्त बनाएगा। यह अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि होगी। एनईपी 2020 उच्च शिक्षा के लिए एक निर्णायक क्षण है और इसका प्रभावी और समयबद्ध कार्यान्वयन ही इसे वास्तव में पथप्रदर्शक बना देगा।

सन्दर्भ सूची

ऐथल, पी. एस.; ऐथल, शुभ्रज्योत्सना (2019) । "भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्ताव 2019 में उच्च शिक्षा का विश्लेषण और इसके कार्यान्वयन की चुनौतियां" । एप्लाइड इंजीनियरिंग और प्रबंधन पत्र के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल। 3 (2): 1-35 । एसएसआरएन 3417517

नंदिनी, एड. (29 जुलाई 2020) । "नई शिक्षा नीति 2020 हाइलाइट्स: बड़े बदलाव देखने के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा" । हिंदुस्तान टाइम्स।

जेबराज, प्रिसिला (2 अगस्त 2020) । "द हिंदू एक्सप्लेन्स| राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या प्रस्तावित है?" । हिन्दू। आईएसएसएन 0971-751X

चोपड़ा, रितिका (2 अगस्त 2020) । "व्याख्या: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढ़ना" । इंडियन एक्सप्रेस।

रोहतगी, अनुभा, एड. (7 अगस्त 2020) । "हाइलाइट्स| एनईपी भारत में अनुसंधान और शिक्षा के बीच की खाई को कम करने में भूमिका निभाएगा: पीएम मोदी" । हिंदुस्तान टाइम्स।

कृष्णा, अतुल (29 जुलाई 2020) । "एनईपी 2020 हाइलाइट्स: स्कूल और उच्च शिक्षा" । एनडीटीवी।

नायडू, एम. वेंकैया (8 अगस्त 2020) । "नई शिक्षा नीति 2020 भारत के शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगी" । टाइम्स ऑफ इंडिया ब्लॉग।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language